

## वहिंगम

हाल ही में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) में रमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS) के साथ एकीकृत 'वहिंगम (VIHANGAM)' नामक एक इंटरनेट-आधारित प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है।

## महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

- यह भारत की प्रमुख कोयला उत्पादक कंपनियों तथा कोल इंडिया लिमिटेड की आठ सहायक कंपनियों में से एक है।
- MCL वर्ष 1999 में स्थापित पर्यावरण के अनुकूल भूतल खनन तकनीक पेश करने वाली पहली कोयला कंपनी थी।

## प्रमुख बडि:

- **परचिय:**
  - इस प्रणाली में एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन (GCS), एक RPAS, 40 Mbps की इंटरनेट लीज़ लाइन और वहिंगम पोर्टल शामिल हैं।
  - यह प्रणाली खनन गतिविधियों के हवाई वीडियो को खानों से इंटरनेट प्लेटफॉर्म तक वास्तविक समय में प्रसारित करने में सक्षम बनाती है, जसिं केवल आईडी और पासवर्ड रखने वाले अधिकृत कर्मियों द्वारा ही वहिंगम पोर्टल के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।
- **रमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS):**
  - RPAS मानवरहित विमान प्रणाली (UAS) का एक सब-सेट है।
  - मानव रहित विमान के तीन सब-सेट हैं- रमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट और मॉडल एयरक्राफ्ट।
    - ड्रोन मानव रहित विमान (Unmanned Aircraft) के लिये एक आम शब्दावली है।
  - ड्रोन को उनके वज़न (मौजूदा नियम) के आधार पर पाँच श्रेणियों में बाँटा गया है-
    - नैनो- 250 ग्राम से कम
    - माइक्रो- 250 ग्राम से 2 कगिरा. तक
    - स्माल- 2 कगिरा. से 25 कगिरा. तक
    - मीडियम- 25 कगिरा. से 150 कगिरा. तक
    - लार्ज- 150 कगिरा. से अधिक
  - रमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट में रमोट पायलट स्टेशन, आवश्यक कमांड और कंट्रोल लकि तथा टाइप डिज़ाइन में नरिदषिट अन्य घटक होते हैं।
- **UAVs का उपयोग करने वाली अन्य पहलें:**
  - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्तर पूर्व (i-Drone) में ड्रोन रसिपांस एंड आउटरीच नाम से एक ड्रोन आधारित वैक्सीन वितरण मॉडल लॉन्च किया है।
  - तेलंगाना सरकार ने एक महत्तवाकांक्षी यानी इस प्रकार की पहली पायलट परियोजना 'मेडसिनि फ़ॉर्म द सकार्ड के परीक्षण के लिये 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) का चयन किया है।
  - अंतरराष्ट्रीय अरद्ध-शुष्क उपकटबिंधीय फसल अनुसंधान संस्थान' (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics-ICRISAT) को कुछ कृषि विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के अलावा कृषि अनुसंधान गतिविधियों के लिये ड्रोन तैनात करने की अनुमति दी गई थी।